मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवा दिवस पर आयोजित होने वाले रोजगार उत्सव की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा, राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार देकर उनके सपनों को साकार करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

युवा दिवस पर 13 हजार 500 से अधिक युवाओं को मिलेगी नियुक्ति की सौगात

31 हजार करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण होगा-मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

जयपुर, 8 जनवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार देकर उनके सपनों को साकार करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि युवाओं में कौशल और उद्यमिता का विकास कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है। मुख्यमंत्री ने कहा, हम आगामी चार वर्षों में चार लाख रोजगार सरकारी व 6 लाख निजी क्षेत्र में देकर, रोजगार के कुल 10 लाख अवसर उपलब्ध करवाएंगे।

शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर युवा दिवस (12 जनवरी) पर आयोजित होने वाले रोजगार उत्सव की तैयारियों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि इस रोजगार उत्सव में राज्य सरकार युवाओं को 13 हजार 500 से अधिक नियुक्तियां देगी। इनमें चिकित्सा विभाग में सीएचओ के 5 हजार 261, वित्त विभाग में कनिष्ठ लेखाकार के 4 हजार 749, गृह विभाग में कांस्टेबल सहित, अन्य के 3 हजार 133, राजस्व विभाग में तहसील राजस्व लेखाकार के 179, शिक्षा विभाग (माध्यमिक) में विविध 159 पद तथा शिक्षा विभाग (प्राथमिक) में अध्यापक लेवल-प्रथम एवं द्वितीय के 76 पदों पर नियुक्तियां शामिल हैं।

■ मुख्यमंत्री ने बताया कि चिकित्सा विभाग में सी.एम.एच.ओ. के 5,261 वित्त विभाग में कनिष्ठ लेखाकार के 4,749, गृह विभाग में कांस्टेबल सहित 3,133, शिक्षा विभाग (माध्यमिक) में 159, शिक्षा विभाग (प्राथमिक) में 76 पदों पर नियुक्तियाँ दी जायेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी दिन 31 हजार 29 करोड रुपये के 73 हजार 39 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा।

शर्मा ने कहा कि देश और विदेश में कुशल एवं योग्य कार्मिकों की भारी मांग की पूर्ति में राजस्थान अहम भूमिका निभा सकता है, इसके लिए अधिकारी युवाओं की शैक्षिणक और कौशलपरक योग्यता तथा विदेश में काम करने के इच्छुक युवाओं का एक डाटाबेस तैयार किया करें, ताकि विदेशी उद्योगों एवं कंपनियों को राज्य सरकार के माध्यम से योग्य एवं कुशल कार्मिक उपलब्ध करवाए जा सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्थापित जो भी उद्योग तथा कंपनी रोजगार देने में राज्य के युवाओं को प्राथमिकता देंगे, उन्हें राज्य सरकार विशेष रूप से प्रोत्साहित करेगी।

इस अवसर पर मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह आनंद कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण प्रवीण गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव पीएचईडी भास्कर ए सावंत, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री) आलोक गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ सहित, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

राजस्थान विधानसभा का सत्र 31 जनवरी से

जयपुर, 8 जनवरी। सोलहवीं राजस्थान विधान सभा का तृतीय सत्र शुक्रवार 31 जनवरी से होगा। विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बुधवार को विधान सभा सत्र की तैयारियों की जानकारी ली। देवनानी ने सत्र से संबंधित आवश्यक निर्देश विधान सभा के अधिकारियों को दिये। देवनानी ने बताया कि 31 जनवरी को प्रात: 11 बजे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे अभिभाषण देने के लिये विधान सभा पहुंचेंगे। विधान सभा पहुँचने पर अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, सदन के नेता एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और विधान सभा के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा राज्यपाल बागडे का स्वागत करेंगे। राज्यपाल को विधान सभा में आरएसी बटालियन द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जायेगा। राज्यपाल को प्रोसेशन के साथ सदन में ले जाया जायेगा।

■ इस सत्र के सभी प्रश्नों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों, विशेष उल्लेख याचिकाओं आदि के जवाब ऑनलाइन दिये जायेंगे।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे द्वारा 31 जनवरी को प्रात: 11 बजे आहूत किये गये सोलहवीं राजस्थान विधान सभा के तृतीय सत्र की अधिसूचना विधान सभा के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा द्वारा बुधवार को जारी की गई।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि सोलहवीं राजस्थान विधान सभा का तृतीय सत्र नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) के तहत, पूर्णरुपेण डिजिटलाइज्ड होगा। विधान सभा को विधायकों द्वारा पूछे गये प्रश्न, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों, विशेष उल्लेख प्रस्तावों, आश्वासनों एवं याचिकाओं के जवाब राज्य सरकार के विभागों द्वारा नेवा एप्लीकेशन के तहत ही ऑनलाइन प्रेषित किया जाना आवश्यक है।

राज्य सरकार के सभी विभागों को विधान सभा द्वारा प्रश्न आदि नेवा एप्लीकेशन के माध्यम से ही ऑनलाइन भेजे जायेंगे।

विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निर्देश पर विधान सभा के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा के नेतृत्व में विधान सभा के प्रशासनिक व तकनीकी अधिकारियों के दल ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में संचालित विधान सभा प्रकोष्ठों के अधिकारियों और कार्मिकों को बुधवार को नेवा एप्लीकेशन पर कार्य करने यथा प्रश्नों एवं प्रस्तावों इत्यादि के उत्तर देने एवं उनके परिचालन की जानकारी का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया।

केवल लोकसभा के लिये गठबंधन था - तेजस्वी

बक्सर, 08 जनवरी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि यह पहले से तय था कि इंडिया गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए है।..आगे देखा जाएगा कि चुनाव प्रचार में जाएंगे या नहीं। बिहार की यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव आज बक्सर पहुंचे। यहां उन्होंने उक्त टिप्पणी की।

बक्सर के सभा कक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन बनने के दौरान यह तय हो गया था कि यह गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए है, विधानसभा चुनाव के लिए यह गठबंधन नहीं है। हालांकि जब उनसे पूछा गया है कि क्या आप चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली जाएंगे तो उन्होंने कहा कि यह तय नहीं है, आगे देखा जाएगा। हालांकि तेजस्वी ने यह भी कहा कि बिहार में हम साथ-साथ हैं।

दरअसल दिल्ली में विधानसभा का चुनाव की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में इंडिया गठबंधन कई खंड में बंटा हुआ नजर आ रहा है।

कट ऑफ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

क्या हमें ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बात कही थी। हाई प्रोफाइल हुसैन पूर्व वाणिज्य सचिव और बुद्धिजीवी थे।

डॉ. चेल्लैया का मत था कि जरुरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी योजना अर्थव्यवस्था की क्षमता को सीमित कर सकती है और ग्रोथ पर इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता हे।

आबिद साहब का मत था कि अर्थव्यवस्था की सभी खिड़कियां खोल देनी चाहिए ताकि ताज़ा हवा अंदर आए और इस प्रक्रिया में अगर मक्खी-मच्छर भी आ जाते हैं तो आने दीजिए हम उनसे निपट लेंगे।

महत्वपूर्ण यह नहीं है कि ग्रोथ हो, बल्कि यह है कि ग्रोथ की गुणवत्ता कैसी है और इसका फैलाव कितना है तथा बिना अधिक दबाव के कब तक बनी रह सकती है। यदि अर्थव्यवस्था ज्यादा तेज हो जाए तो कई क्षेत्रों की क्षमताओं पर दबाव पड़ सकता है, महंगाई बढ़ सकती है और इससे दूरगामी संभावनाएं प्रभावित हो सकती है।

एक दिन में दो कोचिंग छात्रों ने आत्महत्या की

कोटा, 8 जनवरी (निसं)। कोटा में साल की शुरुआत में एक ही दिन में दो कोचिंग छात्रों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों छात्र कोटा में रहकर जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे।

■ कोटा में दो घटनाओं में हरियाणा व मध्य प्रदेश के छात्र ने फांसी लगाई।

पहला मामला जवाहर नगर थाने क्षेत्र का है हॉस्टल स्टाफ ने बताया कि जब वे छात्र के कमरे पर गए तो वह फंदे पर लटका मिला। उन्होंने तुरंत पुलिस और परिवार को सूचना दी। हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला नीरज दो साल से कोटा में रहकर जे.ई.ई. की तैयारी कर रहा था। जवाहर नगर थाना अधिकारी ने बताया कि छात्र राजीव गांधी नगर क्षेत्र में आनंद कुंज रेजिडेंसी में हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल स्टाफ ने बताया कि नीरज मंगलवार शाम अपने दोस्त के साथ बाहर खाना खाने गया था। तनाव में भी नहीं लग रहा था। रात में अटेंडेंस लेने के दौरान उसने कमरा नहीं खोला। रोशनदान से झांककर देखा तब सुसाइड का पता चला। पंखे में हैंगिंग डिवाइस भी लगी हुई है। उसने कुंडे (हुक) से फंदा लगाया। छात्र के पिता बबलू प्रजापत ने कहा उन्हें आत्महत्या की बात पर यकीन नहीं है। उन्होंने कहा, अगर मेरे बच्चे ने पंखे से लटक कर सुसाइड किया है तो न तो पंखे की पंखुड़ियां टूटी न ही पंखा नीचे आया। उसमें इतनी जगह भी नहीं थी कि रस्सी अंदर चली जाए।

दूसरा मामला विज्ञान नगर क्षेत्र का है। विज्ञान नगर थाना अधिकारी मुकेश कुमार मीणा ने बताया कि मध्य प्रदेश के गुना का मृतक अभिषेक कोटा में रहकर जेईई एडवांस की तैयारी कर रहा था। वह अंबेडकर नगर पीजी में रहता था। उसके कमरे में हैंगिंग डिवाइस नहीं लगा हुआ था। मृतक छात्र के शव को एमबीएस अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम में रखवा दिया है। मृतक के परिवार जनों को सूचित कर दिया। परिजनों के कोटा आने पर कारवाई की जाएगी। विज्ञान नगर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

संयुक्त राष्ट्र ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है जिसमें कहा गया है कि इस वर्ष चीन में इससे प्रभावित लोगों की संख्या पिछले वर्ष से कम है।

उन्होंने चीन के आंकडों के हवाले से कहा है कि इस वर्ष अस्पताल में भर्ती होने वाले एचएमपीवी पीड़ितों की संख्या कम हैं, इसे लेकर चीन में आपातकाल नहीं है। उन्होंने कहा कि चीन में यह स्थिति प्रत्येक वर्ष होती है। दिसंबर 2024 के अंत एचएमपीवी से संक्रमण दर 30 प्रतिशत रही है।

50 साल बाद नए ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इस समारोह में शामिल होने के लिए 400 प्रमुख नेता आमंत्रित किये गये हैं, जिनमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य, प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्ष, कांग्रेस विधायक दल के नेता, संसद सदस्य, ए.आई.सी.सी. के महासचिव, सचिव तथा संयुक्त सचिव शामिल हैं।

पार्टी ने कहा, "इंदिरा गांधी भवन को इस तरह से डिज़ायन किया गया है कि वह पार्टी और इसके नेताओं की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा कर सके। इस भवन में प्रशासनिक, संगठनात्मक तथा रणनैतिक गतिविधियों के सुव्यवस्थित संचालन के लिये आधुनिक सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा गया है।"

इन नये भवन का शिलान्यास दिसम्बर 2009 में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. मनमोहन सिंह तथा तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किया था। इस भवन के निर्माण में 15 वर्ष लग गये। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का मुख्यालय 1978 में 24 अकबर में शिफ्ट हुआ था। ज्ञातव्य है कि यह वह दौर था, जब पार्टी, आज़ादी के बाद पहली बार, सत्ता से बाहर हुई थी। आपातकाल के बाद हुये लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी भी हार गई थीं। कांग्रेस टूट भी गई थी तथा इंदिरा गुट के लिये कोई कार्यालय नहीं था। आंध्र प्रदेश के तत्कालीन सांसद, गद्दाम वैंकट स्वामी ने अपना सरकारी आवास, 24 अकबर रोड, पार्टी को दे दिया था। आज़ादी के बाद से कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय 7 जंतर-मंतर रोड पर था। पार्टी कार्यालय सर्वप्रथम 1971 में 5 राजेन्द्र प्रसाद रोड पर तथा इसके बाद 1978 में 24 अकबर रोड पर शिफ्ट हुआ था।

वी. नारायणन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट प्रॉपल्शन विशेषज्ञ हैं। वी नारायणन 1984 में इसरो में शामिल हुए और लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर (एलपीएससी) के निदेशक बनने से पहले विभिन्न पदों पर कार्य किया। प्रारंभिक चरण के दौरान, उन्होंने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में साउंडिंग रॉकेट्स और संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान और ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के ठोस प्रणोदन क्षेत्र में काम किया।

गहलोत ने सभी घोड़े खोल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इस बारे में किसी भी सोच-विचार से पहले, इस प्रश्न का उत्तर जरुरी है।

वरिष्ठ नेताओं और मीडिया में गहलोत के बहुत समर्थक मौजूद हैं तथा इसका प्राथमिक कारण सिर्फ यह है कि वे इन दोनों के बड़े वित्त पोषक हैं।

पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि गहलोत द्वारा पार्टी पर फैंका गया इस प्रकार का पैसा उन्हें गांधी परिवार के लिये विचारणीय एवं स्वीकार्य बना सकता है।

एक पुरानी कहावत है कि राजनीति (असंभव को) संभव बनाने की कला है।

इसके अलावा, गहलोत के विश्वसनीय दायें हाथ, शशिकान्त फिर से दिल्ली पहुँच गये हैं, ताकि वे इस बात पर नजर रख सकें कि कांग्रेस में क्या चल रहा है, तथा इसके साथ ही, पार्टी नेताओं में गहलोत के लिये लामबंदी भी की जा सके।

गहलोत को उनसे फीडबैक मिलता रहता है तथा उसके बाद, वे परिस्थिति के अनुसार, क्रिया/प्रति क्रिया की ओर कदम बढ़ाते हैं।

लेकिन मूल प्रश्न यही बना हुआ है: क्या गांधी परिवार उन पर विश्वास करता है? या क्या ए.आई.सी.सी. में उनकी वापसी सोनिया गांधी के लिये एक तमाचा नहीं होगी कि उन्होंने एक ऐसे आदमी को वापस ले लिया, जिसने उनके नेतृत्व को चुनौती दी थी? यह व्यक्ति उनके (सोनिया) के नेतृत्व के इतने वर्षों में ऐसा करने वाला इकलौता व्यक्ति था।

सड़क दुर्घटना में घायलों का कैशलैस उपचार हो

नयी दिल्ली 08 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को सड़क दुर्घटना में घायलों के लिए मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक कैशलेस उपचार की योजना 14 मार्च 2025 तक बनाने का केंद्र सरकार को निर्देश दिया। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने एस राजसीकरन द्वारा दायर एक मामले पर विचार करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें यह स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार को इस उद्देश्य के लिए कोई और समय नहीं दिया जाएगा।

पीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि वह

■ सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को 14 मार्च तक योजना बनाने के निर्देश दिये।

मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक योजना जल्द से जल्द बनाए और हर हाल में 14 मार्च, 2025 तक यह योजना तैयार करे ताकि घायल सड़क दुर्घटना पीड़ितों को दुर्घटना के शुरुआती समय, यानी गोल्डन आवर में कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जा सके।

पीठ ने आगे कहा, "गोल्डन आवर में कैशलेस उपचार उपलब्ध कराने के लिए योजना बनाने के लिए धारा 162 में किए गए प्रावधान का उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत जीवन के अधिकार को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना है।

इसके अलावा, योजना बनाना केंद्र सरकार का वैधानिक दायित्व है।"

राजस्थान में 10 जनवरी से वर्षा का अलर्ट

कोहरा व सर्दी का प्रकोप जारी, तापमान और गिरने का अनुमान

जयपुर, 08 जनवरी। राजस्थान में इन दिनों हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है और साथ ही राज्य के कई इलाके धुंध और कोहरे की चपेट में हैं। ठंड और कोहरे के कारण लोग अपने घरों में दुबके रहने को मजबूर हैं। जयपुर मौसम केन्द्र के अनुसार, राज्य में आगामी चार से पांच दिन मौसम मुख्यत: शुष्क रहने तथा अधिकांश भागों में न्यूनतम व अधिकतम तापमान में दो से चार डिग्री गिरावट होने की संभावना है।

■ मजबूत पश्चिमी विक्षोम के सक्रिय होने से बीकानेर, जयपुर व भरतपुर संभाग में वर्षा का अनुमान है।

मौसम केन्द्र के प्रवक्ता के अनुसार, बीकानेर, जयपुर व भरतपुर संभाग के कुछ भागों में आगामी तीन दिन कहीं-कहीं घना कोहरा छाने की संभावना है। उन्होंने बताया कि आगामी 10-12 जनवरी को एक और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम केन्द्र के अनुसार बीकानेर संभाग में रविवार को बारिश का दौर शुरू हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार हल्के पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की बारिश होगी। इसके बाद रात के तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिलेगी।

राज्य में शनिवार को सर्वाधिक तापमान चित्तौड़गढ़ में 31.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और न्यूनतम तापमान वनस्थली (टोंक) में 6.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य के एक मात्र पर्वतीय पर्यटक स्थल माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियसदर्ज किया गया।

संभल मंदिर - मस्जिद विवाद की सुनवाई पर रोक

प्रयागराज, 08 जनवरी। संभल के मंदिर मस्जिद विवाद से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की जिला कोर्ट में चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगा दी है। संभल की शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये रोक लगाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी पक्षकारों से जवाब दाखिल करने को कहा है। पक्षकारों को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करना होगा। पक्षकारों के जवाब पर मस्जिद कमेटी को दो हफ्ते में अपना प्रत्युत्तर दाखिल करना होगा।

■ इन्तजामिया कमेटी की याचिका पर हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट से जिला अदालत में चल रही मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगने से मुस्लिम पक्ष को फिलहाल राहत मिली है। जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट में आज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। हाई कोर्ट इस मामले में 25 फरवरी को फिर से सुनवाई करेगी।25 फरवरी को फ्रेश केस के तौर पर मामले की सुनवाई होगी।

संभल की जिला अदालत में 19 नवंबर को हरिशंकर जैन व अन्य की तरफ से मुकदमा दाखिल किया गया था। हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया था कि मुगल काल की शाही जामा मस्जिद उस स्थान पर बनाई गई थी जहां कभी हरिहर मंदिर था।

भारतीय मूल की अनिता...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लिबरल पार्टी के नेतृत्व के लिए चुनाव की तैयारी चल रही है, आनंद को इसमें मजबूत प्रत्याशी माना जा रहा है। आनंद को उनके अनुभव और समावेशी नेतृत्व के कारण ताकतवर माना जा रहा है। हालांकि नेतृत्व का चुनाव कई कारकों पर निर्भर करेगा, जिनमें पार्टी की गतिशीलता, जन समर्थन और लिबरल पार्टी द्वारा आगामी चुनावों के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति प्रमुख है।

अनिता आनंद भारतीय मूल की हैं और अगर वे प्रधानमंत्री बनीं तो कैनडा और भारत के रिश्तों को नई दिशा मिल सकती है, हालांकि दोनों देशों के बीच के गंभीर विवाद के समाधान में सिर्फ उनका नेतृत्व ही काफी नहीं हो सकता है। कई कारक हैं जो द्विपक्षीय सम्बंधों की दिशा प्रभावित करेंगे।

फिर भी आशावादी होने के कई कारण हैं। तमिलनाडु और पंजाब से आए अप्रवासी की पुत्री होने के कारण, वे भारत की चिंताओं व सांस्कृतिक संवेदनाओं के प्रति अधिक जागरुक हो सकती है। उनकी विरासत विश्वास को बढ़ाने व संवाद बहाल करने में पुल का काम कर सकती है।

संकट के प्रबंधन में आनंद का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, कोविड-19 के दौरान टीकों की खरीद में उनकी नेतृत्व क्षमता नज़र आई थी। इससे संकेत मिलता है कि तनावपूर्ण रिश्तों के समाधान में वे व्यवहारिक सोच अपना सकती है। एक ऐसा नेता जो व्यापार, सुरक्षा व पारस्परिक हितों पर ध्यान देगा, वह विवादास्पद मुद्दों का अराजनीतिककरण कर सकता है। भारत जैसे- जैसे विश्व में आर्थिक ताकत के रुप में उभर रहा है, आनंद फ्री ट्रेड एग्रीमैंट वार्ता को फिर से शुरु करने पर प्राथमिकता दे सकती हैं, जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो सकती है।

प्रधानमंत्री के रुप में अनिता को खालिस्तानी तत्वों के सम्बंध में भारत की चिंताओं का समाधान करना होगा। इसके लिए उन्हें प्रभावशाली सिख समुदाय से डील करना होगा।

अगर अनिता में भारत की सम्प्रभुता के लिए खतरा बने हुए आतंकी तत्वों पर कार्यवाही करने की इच्छाशक्ति है और वे व्यापारिक व शैक्षिक सहभागिता बढ़ाती हैं और दोनों देशों के बीच संवाद स्थापित करती हैं तो भारत और कैनडा के सम्बंधों में सुधार की संभावना बढ़ सकती है।

ट्रूडो के नेतृत्व में भारत व कैनडा के सम्बंधों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। खालिस्तानी अलगाववादी तत्वों के प्रति उनके ढीले रुख का भारत हमेशा से आलोचक रहा है। इससे दोनों देशों के सम्बंध बिगड़े थे और ट्रूडो द्वारा कैनडा के नागरिक की हत्या में भारत सरकार पर आरोप लगाने ने रिश्ते और बिगाड़ दिए थे। फ्री ट्रेड एग्रीमैंट वार्ता रद्द करने और मंत्रिमंडल स्तरीय वार्ताएं भी ठप्प पड़ गईं।

विदेश नीति विशेषज्ञों का कहना है कि नेतृत्व परिवर्तन के बाद भी दोनों देशों के बीच वार्ता के लम्बे दौर होने चाहिए, तभी भारत और कैनडा के रिश्तों में भरोसा बहाल हो सकता है। बाहरी कारक, जैसे अमेरिका-भारत और कैनडा -अमेरिका सम्बंधों में हो रहे बदलाव, भी भारत व कैनडा के संबंधों की दिशा तय कर सकते हैं।

तेलुगू भाषी लोगों की प्रतिष्ठा व साख धूल...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अनुदान योजना का दुरुपयोग किया।

समस्त तेलुगू भाषी समुदाय तथा तेलुगू भाषी दोनों राज्यों के लिए यह शर्म की बात है कि अमेरिका में आंध्र व तेलंगाना मूल के लोग ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाए गए। इससे पूरे देश तथा विशिष्ट रूप से, दोनों राज्यों का नाम खराब हुआ।

संयुक्त आंध्र प्रदेश को अक्सर संयुक्त राज्य अमेरिका का 51वां राज्य कहा जाता था, इस राज्य के लोगों की अमेरिका जाने और वहाँ बसने की रुचि को देखते हुए।

हैदराबाद में तो "चिलुकुरु बालाजी" का एक मंदिर भी है जिसकी विशेषता है कि वहाँ प्रार्थना करने से अमेरिका का वीसा मिल जाता है। हैदराबाद में यह मंदिर वीसा मंदिर के नाम से जाना जाता है और हज़ारों की संख्या में वीसा पाने के इच्छुक लोग इस मंदिर में आते हैं और वीसा पाने के लिए विशेष पूजा करते हैं।

सी.एस.आर. अनियमितताओं का स्कैण्डल उजागर होने के बाद, अमेरिकन फैडरल इन्वैस्टिगेशन एजेन्सियों तथा इन्टर्नल रैवेन्यु सर्विस अधिकारियों ने जाँच शुरु कर दी है।

एपल के कई कर्मचारियों, जिनमें मुख्यत: तेलुगू भाषी लोग शामिल हैं, के ऊपर आरोप है कि इन लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित तेलुगू समितियों के साथ मिलीभगत करके एपल की सी.एस.आर. योजना का अनुचित लाभ उठाया है। इस योजना में गैर लाभकारी संगठनों का समर्थन करने की आड़ में, उक्त तेलुगू समितियाँ एपल के कर्मचारियों से दान लेती थीं, जिसके बाद एपल कंपनी समुदाय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के रुप में उतना ही धन संस्थाओं को देती थीं।

जाँच में सामने आया कि इन डोनेशनों में हेराफेरी की गई थी। एपल से, चंदे के बराबर धन प्राप्त करने के बाद, फण्ड्स को कर्मचारियों को वापस दे दिया जाता था। एपल के फायनैंस विभाग द्वारा एक आंतरिक समीक्षा में ये अनियमितताएं सामने आईं। एपल ने इन्टर्नल रैवेन्यु सर्विस को शिकायत की, जिसके बाद अब बर्खास्त किए गए कर्मचारियों की भी जाँच की जा रही है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, तेलुगू एसोसिएशनों ने एपल में काम करने वाले तेलुगूभाषी लोगों से डोनेशन माँगे तथा एक बड़ी योजना के तहत, कम्पनी की सी.एस.आर. की मैचिंग ग्रान्ट्स का अनुचित लाभ उठाया।

धोखाधड़ी के ये कृत्य उस समय प्रकाश में आये, जब एपल के वित्त विभाग ने डोनेशन के रिकॉर्ड्स में विसंगतियाँ तथा भिन्नताएँ पायीं। इसके तुरन्त बाद, अधिकारियों को सचेत कर दिया गया।

इस रहस्योद्घाटन के बाद, एपल ने विस्तृत एवं गहन ऑडिट कराया तथा ऑडिट में एपल के "ग्रान्ट प्रोग्राम" के दुरुपयोग की पुष्टि हो गई।

इस घोटाले का असर बर्खास्त कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं रहा, इससे पूरे अमेरिका में फैले तेलुगू संगठनों तथा टैक-समुदाय में आक्रोश एवं चिन्ता पैदा हो गई है। बहुत से लोग यह प्रश्न कर रहे हैं कि एपल जैसी प्रतिष्ठित कम्पनी में इतनी बड़ी "ब्रीच ऑफ ट्रस्ट" (विश्वास घात) की स्थिति कैसे पैदा हो सकती

■ अब यह "काण्ड" पकड़ा गया तथा अमेरिका के आई.आर.एस. विभाग को इसकी शिकायत की गई और 185 तेलूगू भाषी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। प्रतिष्ठा धूल धुसरित होने से क्या अब आंध्र व तेलंगाना के तकनीकी आई.टी. प्रोफेशनल्स को अमेरिका में प्रवेश के लिये "वीसा" मिलेगा?

है तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं।

लेकिन, भारत या दो तेलुगू भाषी राज्य ऐसे समय पर इस घटना की पब्लिसिटी करना नहीं चाहेंगे, जब अमेरिका में सरकार बदलने वाली है तथा चंद दिन बाद, 20 जनवरी को डॉनल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति पद सँभालने वाले हैं। विशेष बात यह भी है कि ट्रम्प के प्रबल समर्थक तथा "मेक अमेरिका ग्रेट अगेन" (एम.ए.जी.ए.) एक्टिविस्ट्स बहुत से विदेशियों को प्रतिबंधित एवं निर्वासित करना चाहते हैं, क्योंकि उनका आरोप है कि विदेशों से अमेरिका में आ बसे लोगों के कारण, अमेरिकी लोगों के लिये नौकरियाँ ही नहीं रहीं हैं।

अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में भारतीय समुदायों के प्रति नफरत की भावना पहले से ही मौजूद है। इसके अलावा, ऐसी भी रिपोर्ट हैं कि भारतीय मूल के करीब 18,000 लोगों में, जिन्हें अमेरिका में उनके अवैध प्रवेश के कारण निर्वासित किया जा सकता है, एक बड़ा हिस्सा तेलुगूभाषियों का है।

"तेलुगू ऐसोसिएशन ऑफ नार्थ अमेरिका (टी.ए.एन.ए.) जैसी तेलुगू एसोसिएशन्स के स्थानीय नेता संदेह की नज़र से देखे जा रहे हैं। इसके अलावा, इन पर यह भी आरोप है कि जब इस प्रकार की गतिविधियाँ हो रही होती हैं तो इनका ध्यान कहीं और होता है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908